Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 19th March, 2018 and submissions made by Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 19th of March, 2018 will consist of:-

Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- (it contains consideration and passing of (a) The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018, and (b) the Chit Funds (Amendment) Bill, 2018).

Consideration and passing of the following Bills:-

(i) The Dentists (Amendment) Bill, 2017.

(ii) The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2017.

(iii) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017.

(iv) The Consumer Protection Bill, 2018.

(v) The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018.

(vi) The National Sports University Bill, 2017.

(vii) The Major Ports Authorities Bill, 2016.

(viii) The Rights of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017.

(ix) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017.

(x) The Representation of People (Amendment) Bill, 2017.

HON. SPEAKER: Submissions are laid on the Table of the House.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:-

मेहसाना-अहमदाबाद-मेहसाना मीटर गेज ट्रेन लंबे अरसे से बंद है । इसके तहत आबूरोड डेमू तथा पाटन डेमू ट्रेन में कोच की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे अप-डाउन करने वाले कर्मचारी तथा छोटे व्यापारियों को आने-जाने की फ्रिक्वंसी बढ़ेगी ।

गांधीनगर में मेमू इलेक्ट्रिक ट्रेन आ कर ठहरती है। इसको मेहसाना तक बढ़ाया जाए क्योंकि अहमदाबाद-मेहसाना के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का टैस्टिंग भी हो चुका है ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I propose to include the following items in the List of government business for the coming week.

(1) Crisis in Cashew Industry due to the imposition of customs duty and necessity of a comprehensive package for the revival of the Cashew Industry.

(2) Waiver of Road and infrastructure cess for diesel used by mechanised fishing vessels for fishing.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:

1. उत्तर बिहार के कोशी, सीमांचल एवं मिथिलांचल में किसानों के द्वारा मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, लेकिन किसानों को लागत के अनुसार मक्का का मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को मक्का उत्पादन का उचित मूल्य हेतु कोशी प्रमंडल के सुपौल, सहरसा एवं मधेपुरा में मक्का का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के साथ-साथ गुजरात के आनंद मे दुग्ध मिल के साथ बिहार के मधुबनी जिला के मधेपुर में विगत 50 वर्ष पहले दुग्ध मिल खुला था, जो काफी समय पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन आनंद का दूध अभी भी पूरे देश को दूध की आपूर्ति कर रहा है । अत: सुपौल, सहरसा एवं मधेपुरा में मक्का का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के साथ-साथ बिहार के मधुबनी जिला के मधेपुर में दुग्ध मिल को पुन: चालू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए ।

2. आजादी के बाद से अभी तक बिहार के दियारा एवं टाल क्षेत्र को विभिन्न सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप 21वीं सदी

में भी इस इलाके का विकास नहीं हुआ है, लेकिन अगर टाल एवं दियारा क्षेत्र के लोगों को सरकार के द्वारा मछली पालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहायता देकर प्रेरित किया जाये तब आम लोगों को रोजगार के साथ-साथ टाल एवं दियारा क्षेत्र का विकास भी होगा । अत: बिहार के टाल एवं दियारा क्षेत्र मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाने हेतु सख्त विधि नियम बनाया जाये।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की ग्रामीण शाखाएं आवश्यकता के हिसाब से बहुत ही कम हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोगों को लेन देन के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और किराये आदि में काफी खर्च होता और समय की बर्बादी होती है। जानकारी में आया है कि बैंक ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं खोलने के लिए तत्पर हैं, परंतु रिजर्व बैंक उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा है । अत: रिजर्व बैंक द्वारा नई बैंक शाखाएं खोलने में मंजूरी नही दिये जाने का कार्य।

2. भारत सरकार के उपक्रम भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा सरकार की सभी शिक्षण संस्थानों में 2017-18 के वित्तीय वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के 27 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया है जबकि पहले यहां पर आरक्षण की व्यवस्था थी। अगले सप्ताह की कार्यवाही में उक्त दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण नियमों का पालन नहीं किये जाने का कार्य ।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए ।

देश की आजादी के बाद विकास के दृष्टिकोण से राज्यों के अनुभव में काफी भिन्न्ता रही है। जहां कई राज्यों का तेजी से विकास हुआ है, वहीं कई अन्य राज्य अभाव से ग्रसित रहे हैं । योजना आयोग और वित्त आयोग के वित्तीय हस्तांतरण भी राज्यों के बीच के इस अंतर को पाटने में असफल रहे हैं, बिहार जैसे राज्यों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। बिहार राज्य के विभाजन के समय बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में यह प्रावधान किया गया था कि विभाजन के फलस्वरूप बिहार को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों के संदर्भ में एक विशेष कोषांग का उपाध्यक्ष योजना आयोग के सीधे नियंत्रण में गठित होगा और वह बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष अनुशंसा करेगी, लेकिन केंद्र की सरकार के द्वारा इस पर कोई कारवाई नहीं की गई । अत: बिहार राज्य की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर, जैसे गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति आय, औद्योगीकरण और सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना को देखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए।

कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध है एवं इसकी स्थापना 1977 में हुई थी तथा इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में गैर तकनीकीय समूह 'ग' और 'ख' के अराजपत्रित पदों में भर्ती का कार्य करना है, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ आयोग की निष्पक्षता पर सवाल भी उठने लगे हैं। हर साल होने वाली परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक होने की घटना घट रही है, जिससे गरीब और ईमानदार मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होता है । इसी तरह वर्ष 2018 में आयोजित टियर 2 एग्जाम 17 से 22 फरवरी को ऑनलाइन मोड में हुआ था, इसका प्रश्न-पत्र लीक हुआ। अत: गरीब और ईमानदार मेधावी छात्रों के हित में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वर्ष 1994 से अभी तक आयोजित किये गए सभी प्रतियोगिता परीक्षा की उच्च-स्तरीय/सी.बी.आई. जाँच कराई जाये।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए।

औरंगाबाद जिले की प्रत्येक पंचायत में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय रहित घरों/गावों में शौचालय निर्माण हेतु केंद्र द्वारा राशि का आवंटन एवं इसका सीधा लाभ हस्तांतरण (डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) लाभार्थी को दिए जाने की आवश्यकता ।

औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मुख्य रूप से पूर्व मध्य रेलवे के गुरारू, अनुग्रह नारायण रोड, फेसर, रफीगंज, बघोई कुसा, परैया, कष्टा, देवरिया, कुर्हमा, नरेश हाल्ट, एवं इस्माइलपुर आदि स्टेशनों पर रेल यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधायें, विशेषकर शौचालय, यात्री शेड, फुट ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्मों पर पेयजल की व्यवस्था, लाइट एवं पंखे, रेलवे क्रासिंग का आदि का निर्माण शीघ्र कराने की आवश्यकता ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए।

मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्रांतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के फेनहारा प्रखंड में प्रधान मंत्री आवास योजना लाभकों के बीच राशि के भुगतान में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उक्त भ्रष्टाचार के कारण भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पूर्वी चम्पारण जिला के फेनहारा प्रखंड में प्रधान मंत्री आवास योजना में व्याप्त अनियमितता की जांच का कार्य ।

मेरे संसदीय क्षेत्रांतर्गत सीतामढ़ी जिला काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके सुप्पी एवं बेलसंड प्रखंड को आपस में जोड़ने वाले सोनौल से कंसार मार्ग में मोहारी नहर के पास एक पुल का निर्माण हो जाने से उक्त दोनों प्रखंड के कई ग्रामों के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। सीतामढ़ी जिला सोनौल से कंसार मार्ग में मोहारी नहर के पास पुल निर्माण कराये जाने का कार्य।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए :-

मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में स्थित चक्रधरपुर रेलवे प्रबंधक कार्यालय के अधीन आयरन ओर की ढुलाई में रेलवे को करोड़ों रुपये राजस्व में मिल रहे हैं, जो पूरे देश में बिलासपुर रेलवे प्रबंधक के बाद नम्बर दो पर है। परन्तु क्षेत्रीय विकास एवं आसपास के लोगों के कल्याण के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत रेलवे द्वारा कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा है, जबकि सीएसआर के अंतर्गत कुल कमाई का दो प्रतिशत क्षेत्रीय विकास एवं आसपास के कल्याण पर खर्च करना चाहिए। अत: अगले सप्ताह की कार्यवाही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिंहभूम के रेलवे प्रबंधक चक्रधरपुर के क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय लोगों के कल्याण पर सीएसआर के तहत आयरन ओर की ढुलाई में कमाई का दो प्रतिशत खर्च करने का कार्य शामिल किया जाये।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बहुत गरीबी है और नौकरी का पूरा अभाव है। यहाँ की भोली भाली लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने फुसलाकर महानगरों में लाया जाता है और उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। इस कार्य में प्लेसमेंट एजेंसियाँ संलिप्त एवं सक्रिय हैं। विरोध करने पर बदमाशों द्वारा पीटा जाता है। इन प्लेसमेंट एजेंसियों के पास बदमाशों की एक टीम है। इस तरह से देश में प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा मानव तस्करी की जा रही है

और गरीब लोगों के बच्चों को बेचा जा रहा है। अगले सप्ताह की कार्यवाही में प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा करने एवं इस प्रकार की एजेंसियों की पहचान का कार्य।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I propose to include the following items in the List of government business for the coming week.त

The 13,000 crore fraud in the Punjab National Bank caused by the activities of Nirav Modi and Mehul Choksi who have escaped from the country.

The purchase of Rafale Jet fighters 36 in number by the government at a high cost from the French Government as compared to the earlier price fixed by the earlier government.

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I would like to make a submission on the subject of the vacancies in the Indian Railways in the categories reserved for Scheduled Castes and Tribes. A total of 2,22,159 posts are lying vacant in the Indian Railways. Of these, 41,128 are in the category reserved for scheduled Castes/ Tribes. I would like to request the Central Government to initiate a Special Recruitment Drive for the SC/ST categories.

In lieu of the celebration of Women's Day on 8th March, I would like to make a submission on the subject of participation of Indian women in the workforce. India stands at the 87th position in the global Gender

Gap Index, with 27 per cent participation of women in the workforce. It has been estimated that higher participation of women in the workforce can expand India's GDP by 27 per cent and thus, the necessary steps should be taken.